वर्ष-14 - अंक 95
पृष्ट-04 मूल्य : 01 रुपया

सीतापुर
मंगलवार ,14 जुलाई 2026

RNI.No. UHIN/2012/43078

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

swatantraprabhat.com

epaper.swatantraprabhat.com

जो लिखेगा, वही टिकेगा

लखनऊ से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून गाजियाबाद , दिल्ली ,पंजाब , हरियाणा ,चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में विदाई एवं सम्मान समारोह संपन्न 3

होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा सैन्य प्रहार 4

केन की धारा में बहता एक सवाल - क्या इंसान भी विकास का हिस्सा है? 02

हरियाणा के बिल्डर पर SC सख्त, अकाउंट फ्रीज करने और वारंट जारी करने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आज सोमवार को हरियाणा की कंपनी पार्श्वनाथ डेवलपर्स के खिलाफ सख्त निर्देश जारी किए, क्योंकि कंपनी हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (HRERA) के निर्देशों का पालन करने में नाकाम रही थी. कोर्ट ने पार्श्वनाथ हेसा डेवलपर्स लिमिटेड और पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के डायरेक्टरों के बैंक अकाउंट फ्रीज करने और उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया. साथ ही अगली सुनवाई में डायरेक्टर को पेश होने को कहा है. साथ ही, अपने फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि हरियाणा के अधिकारी या तो बिल्डर के साथ मिलीभगत कर रहे थे या अपनी कानूनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह चेतावनी भी दी कि अगर डायरेक्टर अगली तारीख पर पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए जाएंगे.

36 महीने में देना था कब्जा, 2 दशक गुजरे

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस वी. मोहना और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच गुरुग्राम में पार्श्वनाथ एक्सोटिका प्रोजेक्ट के सीनियर सिटिजन होमबायर्स द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. इन लोगों ने करीब 2 दशक पहले ही घर की पूरी कीमत चुका दी थी, लेकिन उन्हें अभी तक अपने फ्लैट का कब्जा नहीं मिल पाया है. जबकि शर्त यह थी कि प्रोजेक्ट पूरा होने की तारीख से 36 महीनों के अंदर कब्जा दे दिया जाएगा. यह समय-सीमा 2013 में पूरी हो गई थी. इस मामले को 'घर खरीदने वालों की मुश्किल स्थिति' को उजागर करने वाला बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'ये रिट याचिकाएं घर खरीदने वालों की उस मुश्किल स्थिति को दिखाती हैं, जिन्होंने 2 दशक से भी अधिक समय पहले घर की पूरी कीमत चुका दी थी, लेकिन अभी तक उन्हें वे घर नहीं मिल सके हैं जिनका वादा किया गया था. '

20 साल पहले 1 करोड़ थी फ्लैट की कीमत

याचिकाकर्ताओं को साल 2006 में अस्थायी रूप से फ्लैट अलॉट किए गए थे और 2007 की शुरुआत में फ्लैट खरीदने के एग्रीमेंट किए गए थे. हर फ्लैट की कीमत 1 करोड़ रुपये से अधिक थी और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2013 में कब्जा मिलना था. हालांकि, जब खरीदार निर्माणस्थल पर गए, तो उन्होंने पाया कि कंस्ट्रक्शन का काम अभी बहुत अधूरा था. स्लो काम से निराश फ्लैट खरीदारों ने साल 2021 में HRERA का रुख किया, जिसने उनके पक्ष में आदेश देते हुए बिल्डर को उचित मुआवजा देने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह गौर किया कि बिल्डर ने कभी उन आदेशों को चुनौती नहीं दी, जिससे वे आदेश अंतिम हो गए.

HRERA के गाइडलाइंस की लगातार अनदेखी

कोर्ट ने कहा, 'बिल्डर HRERA के गाइडलाइंस की लगातार अनदेखी और उल्लंघन कर रहे हैं. नतीजतन, न तो कब्जा दिया गया और न ही कोई उचित मुआवजा दिया गया.' जब बिल्डर आदेश का पालन करने में नाकाम रहे, तो फ्लैट खरीदारों ने 2022 में HRERAके सामने आदेश लागू करवाने की प्रक्रिया शुरू की. कोर्ट ने पाया कि बार-बार कोशिशों के बावजूद, गुरुग्राम कलेक्टर डेवलपर्स से 'एक पैसा भी' वसूल नहीं सके. बेंच ने दर्ज किया कि संबंधित कंपनियों के डायरेक्टरों को HRERAके सामने पेश करने के लिए उनके खिलाफ वारंट जारी किए गए थे. कोर्ट ने उन वारंटों को लागू करने में गंभीर कमियों पर भी ध्यान दिया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हमें यह देखकर चिंता हो रही है कि एक मामले में बेलिफ को कंपनियों में घुसने नहीं दिया गया, जिसके लिए पुलिस की मदद लेनी पड़ी. लेकिन, असरदार मदद न मिलने की वजह से उन निर्देशों का भी पालन नहीं किया गया. कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जा सकी, और इसलिए याचिकाकर्ता अभी भी 2021-22 के अपने पक्ष में आए आदेशों को लागू करवाने के लिए दर-दर भटक रहे हैं. '

डायरेक्टरों के अकाउंट फ्रीज करने का आदेश

लगातार आदेश नही माने जाने के मामले पर संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ हेसा डेवलपर्स लिमिटेड और पार्श्वनाथ डेवलपर्स लिमिटेड के डायरेक्टरों के बैंक अकाउंट फ्रीज करने का आदेश सुनाया. कोर्ट ने प्रतिवादियों को अगले आदेश तक प्रोजेक्ट में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार बनाने या किसी यूनिट का कब्जा सौंपने से भी रोक दिया. साथ ही कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी कलेक्टरों, सभी कमिश्नरों और संबंधित सभी बैंकों को यह पक्का करने का निर्देश दिया कि उसके निर्देशों का सख्ती से पालन हो और कोर्ट में अनुपालन हलफनामे भी दाखिल किए जाएं. बेंच ने कहा कि इस मामले ने रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट को लागू करने में सिस्टम की कमियों को उजागर किया है.

राम मंदिर में सीईओ भर्ती के लिए निकला आवेदन, 50-70 उम्र के लोग ही योग्य..जानिए क्या क्या शत

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस बीच मंदिर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के लिए आवेदन जारी कर दिए गए हैं. इस पद पर आवेदन मांगे गए हैं जिसमें योग्यता के साथ ही सारी जानकारी दी गई है. मुख्य कार्यकारी अधिकारी के लिए योग्य एवं इच्छुक उम्मीदवार searchcommittee.srjbt@gmail.com पर ईमेल के जरिए से अपना आवेदन भेज सकते हैं. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 जुलाई है. जानकारी के मुताबिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद के लिए 50-70 उम्र लोग ही योग्य होंगे. जिस उम्मीदवार को चुना जाएगा, वो तीन साल के लिए इस पद पर बने रहेंगे. उम्मीदवारों की योग्यता की बात करें तो उनके पास स्नातक (graduation) की डिग्री होना अनिवार्य है. उम्मीदवार को धर्म से हिंदू होना जरूरी है. इसके साथ ही हिंदी और अंग्रेजी का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए. किसी बड़ी कंपनी के प्रबंधकीय दायित्व में कार्य करने का कम से कम 20 सालों का अनुभव होना चाहिए है.

सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट

राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. जिसमें इस पोस्ट के बारे में सारी जानकारी दी गई है. पोस्ट में बताया गया है कि ट्रश्वह्व के पद पर सैलरी कितनी होगी, ये आपसी बातचीत के बात तय होगा. इसके अलावा मंदिर के CEO को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगीं, इसका फैसला भी बाद में ही लिया जाएगा. पोस्ट में बताया गया है कि जिन लोगों ने पहले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम किया हो या किसी बड़े मंदिर/हिंदू धार्मिक संस्था के मैनेजमेंट को संभाला हो, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी. इस योग्यता वाले रिटायर्ड अधिकारी भी आवेदन कर सकते हैं.

आवेदन करने की आखिरी तारीख

CEO पद के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 18 जुलाई 2026, शाम 4:00 बजे तक है. इच्छुक उम्मीदवारों को अपना आवेदन ईमेल के जरिए searchcommittee.srjbt@gmail.com पर भेजना होगा. इसके साथ ही आवेदन के दौरान उम्मीदवार को खुद से जुड़ी सारी जानकारी दस्तावेज भी अपलोड करने होंगे. राम मंदिर के ट्रश्वह्व सीधे महामंत्री को रिपोर्ट करेंगे. संगठन के सभी कानूनी, प्रशासनिक और आर्थिक कामों को पूरा करने की जिम्मेदारी ट्रश्वह्व की होगी. इसके साथ ही CEO को ट्रस्ट की जरूरत और उसके हिसाब से कामकाज के बेहतर नियम, तरीके और सिस्टम तैयार करना होगा. पैसों के लेनदेन, अकाउंट सिस्टम और संस्था की जानकारियों में पूरी ईमानदारी, पारदर्शिता और जवाबदेही से रखनी होगी.

संक्षिप्त ख़बरें

वियतनाम में भारतीय पर्यटकों की नाव हादसा: 15 की मौत के बाद कप्तान गिरफ्तार, जांच शुरू

हनोई। वियतनाम के फु क्वोक द्वीप के समीप भारतीय पर्यटकों से भरी स्पीडबोट पलटने के मामले में स्थानीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नाव के 57 वर्षीय कप्तान गुयेन होंग हाई को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के एक दिन बाद रविवार को उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। अधिकारियों के अनुसार, दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। प्रारंभिक जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि हादसा केवल प्रतिकूल मौसम के कारण हुआ या फिर समुद्री सुरक्षा नियमों के पालन में किसी प्रकार की लापरवाही बरती गई थी। पुलिस कप्तान और चालक दल के अन्य सदस्यों से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों के अनुसार, शनिवार दोपहर फु क्वोक के पास स्थित होन मे रुट न्गोआई द्वीप से लौट रही स्पीडबोट तट से करीब 400 मीटर दूर पलट गई। नाव में 32 भारतीय पर्यटक और चार वियतनामी चालक दल के सदस्य सवार थे।

तेज रफ्तार इको वैन की टक्कर से साले-बहनोई की मौत

शाहजहांपुर। जिले के कांट-जलालाबाद मार्ग पर शनिवार देर रात तेज रफ्तार इको वैन की टक्कर से बाइक सवार साले-बहनोई की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों एक शादी समारोह में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, जलालाबाद क्षेत्र के पुरैना गांव निवासी ब्रह्म सिंह (30) और तिलहर क्षेत्र के सरैया गांव निवासी उनके चचेरे साले अंशुक (25) शनिवार रात कांट क्षेत्र के भंडेरी गांव में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। समारोह में जयमाल कार्यक्रम के बाद दोनों बाइक से अपने घर के लिए रवाना हुए। रास्ते में थाना कांट क्षेत्र के बरेंडा मोड़ के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार इको वैन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों करीब 25 फीट दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को देखा, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने मृतकों के पास मिले मोबाइल फोन के माध्यम से उनके परिजनों को घटना की सूचना दी।

वी द लीडर्स' आंदोलन के साथ अन्नामलाई की नई शुरुआत

चेन्नई(एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने पार्टी पद छोड़ने के बाद अपने नए सार्वजनिक अभियान 'वी द लीडर्स' की औपचारिक शुरुआत कर दी। तमिलनाडु के पोल्लाची में आयोजित 'ड्रग-मुक्त पोल्लाची जागरूकता सम्मेलन' में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी के बीच अन्नामलाई ने नशे के खिलाफ जनआंदोलन चलाने और पर्यावरण संरक्षण के लिए 50 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया। सभा को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने युवाओं की भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि 2031 के चुनावों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और इसमें 'जनरेशन-जेड (Gen-Z)' की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि उनके आंदोलन में 17 प्रतिशत महिलाएं शामिल

हैं, जिनमें 14 प्रतिशत की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है, जबकि 54 प्रतिशत सदस्य 35 वर्ष से कम आयु के हैं। अन्नामलाई ने कहा, '2026 के चुनावों में Gen-Z ने बदलाव की शुरुआत की थी और 2031 में भी वही परिवर्तन की सबसे बड़ी ताकत बनेगी। ' पूर्व भाजपा नेता ने कहा कि इस सम्मेलन के लिए किसी को औपचारिक निमंत्रण नहीं दिया गया था और न ही वीआईपी पास या विशेष व्यवस्था की गई थी। इसके बावजूद हजारों लोग स्वेच्छा से कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि 'वी द लीडर्स' किसी एक व्यक्ति का मंच नहीं, बल्कि आम नागरिकों का जनआंदोलन है।

आंदोलन की प्रमुख घोषणाएं

- अन्नामलाई ने अपने आंदोलन के तहत कई प्रमुख लक्ष्य घोषित किए–
- तमिलनाडु को नशामुक्त बनाने के लिए व्यापक जनजागरण अभियान।
- पर्यावरण संरक्षण के तहत 50 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य।
- आंदोलन में वीआईपी संस्कृति पूरी तरह समाप्त, सभी प्रतिभागियों के लिए समान व्यवस्था।
- आम नागरिकों की भागीदारी पर आधारित जनआंदोलन के रूप में संगठन का विस्तार।

नितिन नवीन से मिले नरोत्तम मिश्रा, बोले- पार्टी का फैसला सर्वोपरि, आशुतोष तिवारी के लिए करूंगा प्रचार

भोपाल। मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में जारी चर्चाओं के बीच पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान दतिया सीट पर टिकट वितरण और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होता है और कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, 'टिकट न मिलना इस बात का प्रमाण है कि कोई भी पार्टी से ऊपर नहीं है। पार्टी का स्थान सबसे ऊंचा है और उसका निर्णय दूरदर्शिता के साथ लिया जाता है। '

चीन का मेगा बांध खुद उसके लिए बना खतरा?

नई दिल्ली(एजेंसी)। चीनी वैज्ञानिकों ने तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी पर चीन की विशाल जलविद्युत परियोजना से जुड़े भू-वैज्ञानिक जोखिमों को लेकर नई चिंता जताई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि परियोजना स्थल के नीचे मौजूद एक सक्रिय फॉल्ट लाइन दुनिया के सबसे बड़े जलविद्युत बांध की संरचनात्मक स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर सकती है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (एससीएमपी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह चेतावनी पिछले महीने चीनी भाषा की पत्रिका 'सेडिमेंटरी जियोलॉजी एंड टेथियन जियोलॉजी' में प्रकाशित एक अध्ययन पर आधारित है। यह शोध सरकारी संस्था चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के पर्यवेक्षण में किया गया था।इस अध्ययन में पाया गया कि पाइजेन फॉल्ट, जो पूर्वी हिमालय क्षेत्र में पृथ्वी की ऊपरी सतह में मौजूद एक सक्रिय दरार है, सीधे

उस क्षेत्र के नीचे से गुजरती है जहां तिब्बत के मेतोग काउंटी में मेतोग जलविद्युत स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। यह स्थान उस क्षेत्र से लगभग 50 किलोमीटर पहले है जहां यारलुंग त्सांगपो नदी भारत में प्रवेश करती है। हालांकि शोधकर्ताओं ने परियोजना को बंद करने की मांग नहीं की, लेकिन उन्होंने इंजीनियरों को अधिक मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाने की सलाह दी है। इनमें ढलानों की स्थिरता में सुधार, रिटेनिंग संरचनाओं की स्थापना और भूस्खलन, भू-धंसाव तथा अन्य भू-वैज्ञानिक खतरों को कम करने के उपाय शामिल हैं।

राम मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं में होगा बड़ा बदलाव, समितियों का होगा पुनर्गठन

अयोध्या(एजेंसी)। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से प्रशासनिक स्तर पर व्यापक बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। मंदिर परिसर में विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन कर रही कई समितियों के पुनर्गठन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इसके तहत कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां नए लोगों को सौंपी जाएंगी। सूत्रों के अनुसार, धार्मिक कार्यक्रमों के संचालन, साफ-सफाई, पार्किंग प्रबंधन, लॉकर व्यवस्था, प्रवेश एवं निकास नियंत्रण तथा प्रसाद वितरण सहित श्रद्धालुओं से जुड़ी विभिन्न व्यवस्थाओं की समीक्षा के बाद नई कार्यप्रणाली लागू की जा रही है। इसके तहत कई मौजूदा जिम्मेदारियों में बदलाव किया जाएगा और नए सदस्यों को समितियों में शामिल किया जाएगा। बताया जा रहा है कि हाल के घटनाक्रम के मद्देनजर मंदिर परिसर की व्यवस्थाओं का विस्तृत मूल्यांकन किया गया। समीक्षा के आधार पर संचालन प्रणाली को अधिक व्यवस्थित और उत्तरदायी बनाने के लिए समितियों का पुनर्गठन किया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं

19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक, सरकार बताएगी विधायी एजेंडा

नई दिल्ली(एजेंसी)। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत से एक दिन पहले 19 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। अधिकारियों के अनुसार, यह बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। संसद के प्रत्येक सत्र से पहले आयोजित होने वाली इस बैठक में सरकार अपने विधायी एजेंडे की जानकारी देगी, जबकि विपक्षी दल उन मुद्दों को सामने रखेंगे जिन्हें वे सत्र के दौरान उठाना चाहते हैं। अधिकारियों का कहना है कि सरकार का विधायी एजेंडा इस बार काफी व्यापक है और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की

संभावना है। वहीं, हाल के हफ्तों में कुछ विपक्षी दलों में सामने आए मतभेद और विभाजन के कारण सत्र के हंगामेदार रहने के भी आसार हैं।विधानसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में उथल-पुथल देखने को मिली है। पार्टी के 20 सांसदों ने 'नेशनल सिटिजन्स पार्टी ऑफ इंडिया' में विलय कर लिया है। इन सांसदों ने लोकसभा में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग भी की है। इसके अलावा, पार्टी के तीन सांसदों ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देकर भाजपा का दामन थाम लिया है।शिवसेना (यूबीटी) में भी विभाजन हुआ है। लोकसभा में पार्टी के छह सांसद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वहीं, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सात सांसद पहले ही भाजपा में शामिल हो चुके हैं। मॉनसून सत्र के दौरान विपक्ष की ओर से NEET-UG पेपर लीक का मामला और ऑपरेशन सिंदूर में हुई हताहतों को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणियों का मुद्दा उठाए जाने की संभावना है। कांग्रेस ने इस संबंध में रक्षा मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा।

अगले वर्ष शुरू होगा पहला हाई-स्पीड रेल सेक्शन

बुलेट ट्रेन परियोजना को मिली रफ्तार

नई दिल्ली(एजेंसी)। देश की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय रेल मंत्री ने हैदराबाद में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल परियोजना का निर्माण तेजी से चल रहा है और इसका पहला परिचालन खंड सूरत से बिलीमोरा के बीच अगले वर्ष शुरू कर दिया जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि परियोजना को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। पहले वापी-सूरत, फिर वापी-अहमदाबाद, इसके बाद अहमदाबाद-ठाणे और अंत में अहमदाबाद-मुंबई खंड को परिचालन के लिए तैयार किया जाएगा। परियोजना पूरी होने के बाद देश में हाई-स्पीड रेल नेटवर्क

की नई शुरुआत होगी और प्रमुख शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। रेल मंत्री के अनुसार, प्रस्तावित हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के शुरू होने के बाद देश के कई प्रमुख शहरों के बीच सफर पहले की तुलना में काफी तेज होगा। उन्होंने बताया कि पुणे से हैदराबाद की यात्रा लगभग 2 घंटे, हैदराबाद से मुंबई करीब 2 घंटे 50 मिनट, हैदराबाद से अमरावती 1 घंटा 10 मिनट, हैदराबाद से चेन्नई लगभग 3 घंटे और हैदराबाद से बेंगलुरु करीब 2 घंटे 35 मिनट में पूरी की जा सकेगी। रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हैदराबाद के लिए तीन नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की योजना बनाई गई है। इनमें पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद-चेन्नई और हैदराबाद-बेंगलुरु बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शामिल हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर हैदराबाद देश के प्रमुख हाई-स्पीड रेल हब के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि इन कॉरिडोरों से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी, निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा दक्षिण भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। रेल मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तेलंगाना के लिए 5,400 करोड़ रुपये का रेलवे बजट आवंटित किया गया है। यह निवेश राज्य के रेल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने, नई परियोजनाओं को गति देने और भविष्य की हाई-स्पीड रेल योजनाओं के लिए आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगे वाहन

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण आज

लखनऊ(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच आवागमन अब और तेज एवं सुगम होने जा रहा है। करीब 3,600 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे का लोकार्पण सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने उद्घाटन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। एक्सप्रेसवे पर वाहन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से दौड़ सकेंगे, जिससे लखनऊ से कानपुर का सफर महज 30 से 35 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का लाभ केवल लखनऊ और कानपुर ही नहीं, बल्कि सीतापुर, हरदोई, अयोध्या और सुल्तानपुर जैसे जिलों के यात्रियों को भी मिलेगा।

एनएचएआई के अनुसार, एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। मार्ग पर चार बड़े पुल, 25 छोटे पुल, चार फ्लाईओवर, 11 पैदल अंडरपास और हल्के वाहनों के लिए 13 अंडरपास बनाए गए हैं। हादसे की स्थिति में त्वरित राहत उपलब्ध कराने के लिए पूरी सड़क पर 63 सीसीटीवी कैमरे और 16 वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन सिस्टम लगाए गए हैं। किसी भी दुर्घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और 15 मिनट के भीतर रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच सकेगी। पूरे एक्सप्रेसवे की निगरानी एक केंद्रीय कंट्रोल सेंटर से की जाएगी।

संपादकीय

जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना कितना सार्थक?

देश में जब भी किसी बड़ी परीक्षा को लेकर विवाद खड़ा होता है, तब उसका असर केवल छात्रों तक सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र, सरकार और समाज पर पड़ता है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) भी पिछले कुछ वर्षों से लगातार विवादों के केंद्र में रही है। प्रश्नपत्र लीक, परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल, परिणामों को लेकर विवाद और पारदर्शिता की मांग ने लाखों छात्रों और उनके अभिभावकों को चिंतित किया है। इसी पृष्ठभूमि में जंतर-मंतर पर सीजेपी द्वारा नीट छात्रों के समर्थन में दिया गया धरना चर्चा का विषय बना। सवाल यह है कि क्या इस तरह का धरना वास्तव में छात्रों के हित में सार्थक साबित होता है या यह केवल राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने का माध्यम बनकर रह जाता है। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार- भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखने और विरोध दर्ज कराने का अधिकार देता है। जंतर-मंतर लंबे समय से देश में जन आंदोलनों का प्रमुख केंद्र रहा है। जब लाखों छात्र किसी परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी बात पर्याप्त रूप से नहीं सुनी जा रही, तब शांतिपूर्ण धरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा माना जा सकता है। यदि धरने का उद्देश्य छात्रों की वास्तविक समस्याओं को सरकार और संबंधित संस्थाओं तक पहुंचाना हो, तो इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था की सकारात्मक अभिव्यक्ति कहा जा सकता है। छात्रों की आवाज को मिला मंच- धरने का सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वह बिखरी हुई आवाजों को एक मंच देता है। देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले छात्र अपनी समस्याओं को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं उठा पाते, लेकिन किसी सामूहिक आंदोलन के माध्यम से उनकी मांग राष्ट्रीय बहस का विषय बन जाती है। नीट जैसी परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों छात्र वर्षों की तैयारी करते हैं। ऐसे में यदि परीक्षा प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं, तो उनका मानसिक तनाव और भविष्य की चिंता स्वाभाविक है। धरने के माध्यम से यही संदेश दिया जाता है कि छात्रों की मेहनत और भविष्य सर्वोपरि है। सरकार और संस्थाओं पर बढ़ता है दबाव- लोकतांत्रिक आंदोलनों का एक उद्देश्य जवाबदेही तय करना भी होता है। जब किसी परीक्षा को लेकर व्यापक विरोध होता है, तो संबंधित एजेंसियों और सरकार पर जांच कराने, सुधार लागू करने और पारदर्शिता बढ़ाने का दबाव बनता है। यदि धरने के कारण परीक्षा प्रणाली में सुधार, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, पेपर लीक रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो आंदोलन को सार्थक कहा जा सकता है। केवल विरोध नहीं, समाधान भी जरूरी- किसी भी आंदोलन की सफलता केवल भीड़ जुटाने से तय नहीं होती। यदि धरने के दौरान परीक्षा सुधार, तकनीकी सुरक्षा, पारदर्शी जांच, समयबद्ध कार्रवाई और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम जैसे ठोस सुझाव दिए जाएं, तो उसका प्रभाव कहीं अधिक सकारात्मक होता है। सिर्फ परीक्षा रद्द करने या विरोध दर्ज कराने से आगे बढ़कर शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने पर भी ध्यान देना आवश्यक है। राजनीतिक हस्तक्षेप पर उठते हैं सवाल- ऐसे आंदोलनों में अक्सर विभिन्न राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन भी शामिल हो जाते हैं। इससे आंदोलन को व्यापक समर्थन तो मिलता है, लेकिन कई बार आरोप लगते हैं कि छात्रों के मुद्दों का राजनीतिक लाभ उठाया जा रहा है। यदि किसी भी संगठन का उद्देश्य वास्तव में छात्रों के हितों की रक्षा करना है, तो आंदोलन को राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से ऊपर रखते हुए केवल शिक्षा सुधार और छात्रों के अधिकारों पर केंद्रित रहना चाहिए। छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव- नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र पहले से ही अत्यधिक दबाव में रहते हैं। परीक्षा विवाद और लगातार चल रहे आंदोलनों का असर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसलिए किसी भी आंदोलन को इस प्रकार संचालित किया जाना चाहिए कि छात्रों में अनिश्चितता और भय बढ़ने के बजाय उन्हें भरोसा मिले कि उनकी समस्याओं का समाधान खोजा जा रहा है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता- नीट विवाद ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि केवल परीक्षा आयोजित करना पर्याप्त नहीं है। आवश्यक है कि पूरी प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक, मजबूत साइबर सुरक्षा, प्रश्नपत्र की गोपनीयता, परीक्षा केंद्रों की निगरानी और निष्पक्ष जांच व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए। यदि आंदोलन इन सुधारों की दिशा में सरकार और संबंधित संस्थाओं को ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है, तो उसका दीर्घकालिक प्रभाव सकारात्मक हो सकता है नीट छात्रों के समर्थन में जंतर-मंतर पर सीजेपी का धरना लोकतांत्रिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा सकता है, बशर्ते उसका उद्देश्य छात्रों के हितों की रक्षा, परीक्षा प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता सुनिश्चित करना हो। किसी भी आंदोलन की वास्तविक सफलता इस बात से तय होती है कि उसके परिणामस्वरूप क्या ठोस बदलाव हुए, क्या छात्रों का विश्वास बहाल हुआ और क्या भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। अंतत: यह याद रखना होगा कि नीट केवल एक परीक्षा नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के सपनों और भविष्य से जुड़ा विषय है। इसलिए सरकार, परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियों, न्यायपालिका, सामाजिक संगठनों और छात्रों—सभी की साझा जिम्मेदारी है कि परीक्षा प्रणाली को निष्पक्ष, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाया जाए। तभी किसी भी धरने या आंदोलन की सार्थकता वास्तविक अर्थों में सिद्ध होगी।

राजीव शुक्ला -(संपादक)

केन की धारा में बहता एक सवाल - क्या इंसान भी विकास का हिस्सा है?

करीब 23 लाख पेड़ प्रभावित होने और केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलकर जल बेतवा में भेजने की आशंका है। सरकार के अनुसार इससे 10.62 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई, 62 लाख लोगों को पेयजल और 103 मेगावाट बिजली मिलेगी। लेकिन गोंड और कोल आदिवासियों के लिए यह केवल विकास नहीं, बल्कि अस्तित्व का सवाल है। उनके लिए जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, बल्कि इतिहास, संस्कृति, आजीविका और पहचान का आधार है। वादों और ज़मीनी हकीकत की दूरी ने चिता आंदोलन फिर सुलगा दिया। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद कई गाँवों में मकान तोड़े गए, बिजली कनेक्शन काटे गए, स्कूल ढहाए गए और विरोध करने वालों पर मुकदमे दर्ज हुए। दिव्या अहिरवार, लक्ष्मी आदिवासी सहित कई महिलाएँ विरोध में डटी रहीं, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर अनशन पर बैठे। उनका दावा है कि 7,000 से अधिक परिवार (लगभग 35-50 हजार लोग) विस्थापन की कगार पर हैं। उनके अनुसार संकट केवल घरों का नहीं, बल्कि जल, जंगल, जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान का है। सवाल है—यदि विकास की कीमत आदिवासी समाज चुकाए और लाभ दूसरों को मिले, तो क्या यह न्यायपूर्ण विकास कहलाएगा? इस संघर्ष का दायरा केवल विस्थापन नहीं, पूरे पारिस्थितिकी तंत्र तक है। पन्ना टाइगर रिजर्व का बड़ा हिस्सा डूबने की आशंका है, जिससे बाघों की पुनर्स्थापना, घड़ियाल संरक्षण और गिद्धों के प्राकृतिक घोंसले संकट में पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार वृक्ष कटाई और पारिस्थितिकी परिवर्तन से क्षेत्रीय वर्षा में करीब 12 प्रतिशत कमी आ सकती है। केन नदी का प्राकृतिक प्रवाह बदलने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ने की आशंका है। आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिक भी इसके प्राकृतिक तंत्र पर प्रभाव की चेतावनी दे चुके हैं। इसलिए आदिवासियों का 'जंगल हमारा, नदी हमारी' कहना विकास विरोध नहीं, बल्कि प्रकृति और भविष्य की चिंता है। किसी भी विस्थापन की सबसे बड़ी कीमत आँकड़े नहीं, इंसानी ज़िंदगियाँ चुकाती हैं। केन-बेतवा परियोजना भी इसी सच्चाई के सामने है। आधिकारिक आँकड़ों के अनुसार 7 हजार से अधिक परिवार प्रभावित होंगे और 22 गाँव डूब क्षेत्र में समा जाएँगे। पुनर्वास को लेकर असंतोष है। किसी को साढ़े बारह लाख, तो किसी को केवल साढ़े सात लाख रुपये मुआवजा मिल रहा है। वयस्क सदस्यों को अलग परिवार का दर्जा देने की माँग अधूरी है। आदिवासी समाज नकद नहीं, 'भूमि के बदले भूमि' चाहता है, क्योंकि जंगल और खेत उसके जीवन का आधार हैं। आंदोलनकारियों का आरोप है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। पर्याप्त सूचना बिना मकान तोड़े जाने से प्रशासन और समाज के बीच भरोसे की खाई गहरी हुई है। तस्वीर का दूसरा पहलू भी अहम है। सरकार का तर्क है कि भविष्य की जल जरूरतों के लिए बड़े समाधान जरूरी हैं। सिंचाई, पेयजल और बिजली जैसी बुनियादी जरूरतों को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल है कि किसी परियोजना का मूल्य केवल लाभ से तय होगा या उसकी सामाजिक और पर्यावरणीय कीमत से भी। केन-बेतवा परियोजना ने फिर बहस छेड़ी है कि नदी जोड़ो योजनाएँ तभी सफल होंगी, जब वे स्थानीय परिस्थितियों, पारिस्थितिकी और समाज की जरूरतों के अनुरूप हों। केवल इंजीनियरिंग समाधान, प्रकृति और समुदाय की सहमति बिना, स्थायी नहीं हो सकते। विकास तभी सार्थक है, जब लाभ और कीमत का न्यायपूर्ण संतुलन हो। बड़ी परियोजनाओं के साथ छोटे, टिकाऊ विकल्प भी जरूरी हैं। विशेषज्ञ वर्षा जल संचयन, छोटे बाँध, जलग्रहण प्रबंधन और स्थानीय जल संरक्षण को बेहतर समाधान मानते हैं। सवाल है कि मध्य प्रदेश अपने जंगलों, वन्य संपदा और जल संसाधनों की कीमत चुका रहा है, जबकि लाभ का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश को मिलेगा। सर्वोच्च न्यायालय की सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी ने भी परियोजना की पर्यावरणीय और आर्थिक व्यवहार्यता पर गंभीर आपत्तियाँ दर्ज की थीं, लेकिन उन्हें महत्व नहीं मिला। यदि बड़े निर्णयों में वैज्ञानिक चेतावनियाँ, स्थानीय अनुभव और न्यायपूर्ण पुनर्वास उपेक्षित रहें, तो विकास का दावा संदेह के घेरे में आता है। लोकतंत्र की शक्ति केवल निर्णय में नहीं, असहमति सुनने में भी है। पन्ना और छतरपुर से उठता यह संघर्ष अब केवल कुछ गाँवों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह सवाल उठाता है कि भारत का विकास प्रकृति और मानव के संतुलन के साथ होगा या जंगलों और संस्कृतियों की कीमत पर। आदिवासी महिलाओं का संघर्ष केवल मुआवजे का नहीं, बल्कि सम्मान, अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों का है। सरकार को पारदर्शी पुनर्वास, प्रभावी पर्यावरणीय समीक्षा और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। पन्ना टाइगर रिजर्व के नुकसान की भरपाई के लिए ग्रेटर पन्ना लैंडस्केप प्लान के तहत 47,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन विकास प्रस्तावित है। इतिहास बाँधों की ऊँचाई नहीं, बल्कि कमजोर वर्गों के साथ राष्ट्र के व्यवहार को याद रखता है। विकास तभी टिकाऊ होगा, जब वह प्रकृति और लोगों की सहमति से आगे बढ़े।

प्रो. आरके जैन 'अरिजीत'

विशेषज्ञों का अध्ययन दूर करेगा इथेनॉल के भ्रम

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल को तेज़ी से बढ़ावा देने की सरकारी नीति हाल के हफ़्तों में लोगों की कड़ी आलोचना का निशाना है, हालांकि, यह नीति 2022 से लागू है। 20 प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का मूल लक्ष्य 2030 तक हासिल करना था, लेकिन समयपूर्व 2025 कर दिया गया। इस नीति के फ़ायदों के बारे में कई दावे किए जा रहे हैं—ऊर्जा सुरक्षा और विदेशी मुद्रा की बचत से लेकर किसानों के कल्याण तक। फिर भी, वाहन मालिक इंजन खराब होने और माइलेज कम होने की शिकायत कर रहे हैं। अपने बचाव में, सरकार का कहना है कि यह नीति सबूतों पर आधारित है और डेटा समर्थित है, जिसमें अधिकांशत: पेट्रोलियम संगठनों के बेनामी और अप्रकाशित अध्ययनों का हवाला दिया गया है।वाहनों पर इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के असर के दावों को साबित करने के लिए कोई स्वतंत्र अथवा विशेषज्ञों द्वारा जांचा-परखा अध्ययन मौजूद नहीं है। अगर इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाली कारों की फ़्यूल एफ़िशिएंसी (ईंधन दक्षता) कम है—जैसा कि अब कार निर्माता भी मान रहे हैं—और इंजन खराब हो रहे हैं—जैसा कि वाहन मालिक शिकायत कर रहे हैं—तो इससे आर्थिक लागत बढ़ेगी। इसके अलावा, कृषि एवं खाद्य विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इथेनॉल मिश्रण से खाद्य सुरक्षा पर असर पड़ेगा, क्योंकि किसान खाद्य फ़सलों के बजाय ज़्यादा पानी खर्च करने वाली गन्ने की खेती की ओर बढ़ रहे हैं। इथेनॉल की बढ़ती मांग के मद्देनजर निर्माता कंपनियां मक्का और चावल का इस्तेमाल कच्चे माल के तौर पर कर रही हैं। सरकार को नीति के लक्ष्यों के बारे में स्पष्ट होना जरूरी है और इसके फ़ायदों के बारे में ठोस सबूत पेश करने चाहिए, न कि आलोचकों पर गलत इरादे का आरोप मढ़ देना या इसके नकारात्मक प्रभावों को लेकर लोगों के गुस्से को नज़रअंदाज़ करना।लोग अक्सर ब्राज़ील का उदाहरण देते हैं, जहां 1980 के दशक में इथेनॉल मिश्रण शुरू किया गया था। इसके दीर्घकालीन असर अब जाकर सामने आ रहे हैं। यह नीति 1970 के दशक में चीनी के फालतू उत्पादन का सीधा नतीजा थी और इसे चीनी लॉबी के दबाव में शुरू किया गया था। पिछले चार दशकों में, इसने वहां ज़मीन के इस्तेमाल में भारी बदलाव किया है, नतीजतन, ईंधन फ़सलों के लिए जगह बनाने के वास्ते अमेज़न के जंगलों की कटाई के कारण भारी मात्रा में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ है। वैसे भी, बड़े पैमाने पर ऊर्जा फ़सलों की खेती के लिए भारत की जलवायु और मिट्टी की स्थिति ब्राज़ील जैसी नहीं है। किसी भी नई तकनीक की तरह, ग्रीन तकनीक को भी—चाहे वह इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल हो या इलेक्ट्रिक गाड़ियां—व्यापक पैमाने पर लागू करने पर अनचाहे बुरे असर हो सकते हैं। जैसे किसी नई वैक्सीन या दवा को लाने से पहले क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, वैसे ही सभी नई तकनीकों का अलग-अलग स्थितियों में कुछ समय तक फील्ड-टेस्ट किया जाना चाहिए, और उससे मिले डेटा का विश्लेषण करवाने को स्वतंत्र विशेषज्ञों को दिया जाए। परिवहन अर्थव्यवस्था का एक अहम अंग है, और किसी भी नई तकनीक को लागू करने से पहले उसकी कई पहलुओं से जांच होनी चाहिए और सिर्फ़ वाहन निर्माता ही नहीं, बल्कि सभी हितधारकों के साथ उस पर चर्चा होनी चाहिए। यह काफी चौंकाने वाली बात है कि सरकार ने अपने बचाव में वाहन निर्माता कंपनियों को उन शिकायतों का जवाब देने के लिए बुलाया—जो वाहन का उपयोग करने वाले कह रहे हैं—जैसे कि माइलेज में कमी और गाड़ियों के धातु एवं रबर पुर्जों का खराब होना। दुनिया भर में वाहन निर्माता डेटा में हेरफेर करने के लिए कुख्यात हैं, जैसा कि 2015 में अमेरिका में फॉक्सवैगन एमिशन स्कैंडल में यह सामने आया था। कार बनाने वाली इस कंपनी ने अपनी कारों के डीज़ल इंजन को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया था कि टेस्टिंग के दौरान उत्सर्जन सीमा नियंत्रण में दिखे ताकि नियामक मानकों पर खरा उतरता दिखाई दे; नतीजतन, 40 गुना ज़्यादा प्रदूषण पैदा करने वाली कारों को भी मानकों के भीतर पाया मानकर स्वीकृति दे दी गई। अगर पेट्रोलियम मंत्री के दावे के मुताबिक इथेनॉल नीति वाकई वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, तो सरकार को उन तमाम अध्ययनों के नतीजे सार्वजनिक करने चाहिए, जो ईंधन की क्षमता, अलग-अलग पुर्जों और इंजन पर मिश्रित ईंधन के दीर्घकालीन प्रभाव और अलग-अलग तरह की गाड़ियों पर अलग-अलग परिचालन स्थितियों में परीक्षण डेटा को जांचने के लिए किए गए हों। इसके अलावा, हमें इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के पर्यावरण के अनुकूल होने के बारे में वैज्ञानिक सुबूत चाहिए, जो कि इथेनॉल के संपूर्ण पर्यावरणीय एवं कार्बन फुटप्रिंट पर आधारित हो — यानी कच्चे ईंधन के उत्पादन से लेकर कारों में वास्तविक इस्तेमाल होने तक। फिर, हमें मिश्रित ईंधन के इस्तेमाल करने पर लागत-लाभ विश्लेषण की ज़रूरत है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि माइलेज गिरने की चिंताएं हैं। अगर माइलेज 5 प्रतिशत भी कम हो जाती है और कार उपयोग करने वालों को ज़्यादा पेट्रोल खरीदना पड़ता जाए, तो आर्थिक फ़ायदों और विदेशी मुद्रा की बचत के दावे हवा हो जाते हैं।

मेष -इस सप्ताह मेष राशि के जातकों को शुरुआत में धन का लाभ मिल सकता है। कामकाज को लेकर स्थिति अच्छी बनी रहेगी। हफ्ते के दूसरे भाग में कामकाज से संबंधित यात्रा का योग बन सकता है। धन खर्च का योग भी रहेगा।

वृषभ : इस सप्ताह वृषभ राशि के जातकों को नौकरी से संबंधित अच्छे लाभ मिल सकते हैं। धन लाभ को लेकर इस हफ्ते आपके लिए स्थितियां अच्छी बनी रहेंगी। इस हफ्ते आप मित्रों के साथ आनंददायक समय व्यतीत कर सकते हैं। छात्र वर्ग के लिए यह हफ्ता लाभ देने वाला बना रहेगा।

मिथुन: इस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों को नौकरी के क्षेत्र में अच्छे फल मिलने की संभावना रहेगी। इस राशि से संबंधित जो जातक नौकरी की तलाश में है उनको सफलता मिल सकती है तथा चल रही जॉब में प्रमोशन मिल सकता है।

कर्क : इस सप्ताह कर्क राशि के जातकों को शुरुआत में कुछ समस्या हो सकती है, किन्तु हफ्ते के बाकी दिनों में आपको सफलता मिलेगी। इस हफ्ते भाग्य का सहयोग आपके अधूरे कार्य पूर्ण करा सकता है। कुछ जातकों की नौकरी की तलाश इस हफ्ते खत्म हो सकती है।

सिंह : इस सप्ताह सिंह राशि के जातकों की शुरुआत अच्छी होगी। हफ्ते के मध्य में आपको सेहत संबंधी कोई समस्या परेशान कर सकती है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते किसी तरह का बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। इस हफ्ते कामकाज को लेकर आपका आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा।

कन्या: इस सप्ताह कन्या राशि के जातकों को कोई पुराना धन मिल सकता है। इस हफ्ते आपको माता-पिता को लेकर कोई चिंता बनी रह सकती है। कामकाज के लिहाज से हफ्ता आपको अच्छे फल दे सकता है। पारिवारिक जीवन में आनंद बना रहेगा तथा पारिवारिक सदस्यों का सहयोग आपको मिलेगा।

तुला : इस सप्ताह तुला राशि के जातकों को अच्छा धन का लाभ प्राप्त हो सकता है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपके लिए स्थिति अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते लाभ को लेकर चल रहे प्रयासों में आपको अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। हफ्ते के मध्य में पारिवारिक

वृश्चिक: इस सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों को अपनी किसी परेशानी में राहत मिल सकती है। धन लाभ के लिहाज से हफ्ता आपके पक्ष में बना रहेगा। इस हफ्ते आपकी आय के स्रोत में वृद्धि के योग बनेंगे। आपका पारिवारिक तथा वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा।

धनु : यह सप्ताह धनु राशि के जातकों की शुरुआत अच्छी होगी। इस हफ्ते आप अपनी माता को लेकर कुछ चिंतित हो सकते है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते सहकर्मियों के साथ सामंजस्य बना कर चलना आपको सफलता दे सकता है।

मकर : इस सप्ताह मकर राशि के जातकों को धन का लाभ उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएगा। इस हफ्ते कामकाज को लेकर आपका आत्मविश्वास बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा। अपने पराक्रम के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे।

कुंभ : इस सप्ताह कुंभ राशि के जातकों को कुछ अच्छे कार्य प्राप्त हो सकते हैं। इस हफ्ते आपकी दिनचर्या में कुछ बदलाव हो सकते हैं। कामकाज को लेकर स्थिति मजबूत बनी रहेगी।

मीन : इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को शुरुआत में कुछ दिक्कतें हो सकती है। कार्यक्षेत्र में इस हफ्ते आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी। इस हफ्ते आपको अच्छे लाभ मिलने की संभावना बनेगी। संतान तथा जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम भाव बढ़ेगा। इस हफ्ते आपको व्सकती है। आय में वृद्धि के योग रहेंगे।

विधिक बिरादरी के लिए 'वेकअप कॉल'

इसके साथ ही, कानूनी क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे दूर करना समय की मांग है। आज के आधुनिक वकील के लिए ई-कोर्ट्स, वर्चुअल हियरिंग, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और कानूनी डेटा विश्लेषण में दक्ष होना केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इसके अलावा, अदालती शिष्टाचार, मुवक्किल के प्रति जवाबदेही और अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर नैतिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस पेशे की गरिमा हमेशा बनी रहे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 'मैन्डेटरी कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन' लागू है। वहां वकीलों के लिए अपने लाइसेंस को बनाए रखने हेतु हर साल निश्चित घंटों की कानूनी शिक्षा या सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसी तरह, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बार एसोसिएशन और सरकार के सहयोग से 'निरंतर पेशेवर विकास' कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया जाता है, जहां इन क्रेडिट्स को पूरा न करने पर वकील के अभ्यास करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित तक किया जा सकता है।भारत में कानूनी पेशे का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन गुणवत्ता उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है।

कानून स्थिर नहीं है, यह जीवित है और समय के साथ बदलता रहता है। एक वकील के लिए उसकी डिग्री केवल एक प्रवेश द्वार है, लेकिन असली परीक्षा अदालत के फर्श पर हर दिन होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में 'अजय विज बनाम इंडियन बैंक्स एसोसिएशन' (2026) मामले में जो टिप्पणी की, वह महज एक न्यायिक आदेश नहीं है, बल्कि भारतीय विधिक बिरादरी के लिए एक अत्यंत गंभीर 'वेकअप कॉल' है। यह मामला केवल एक वकील का निजी विवाद नहीं, बल्कि भारतीय न्याय प्रणाली की एक गंभीर खामी को उजागर करने वाला एक ऐतिहासिक घटनाक्रम है। एक वकील की कानूनी राय को 'लापरवाही' मानकर उसे 'कॉशन लिस्ट' में डालना, वकील की बदलती भूमिका और उसकी व्यावसायिक जवाबदेही पर बड़े प्रश्नचिह्न लगाता है। यह निर्णय बताता है कि वकील अब केवल अपने मुवक्किल का पक्ष रखने वाला व्यक्ति नहीं रह गया है, बल्कि वह एक 'विशेषज्ञ' बन गया है, जिसकी एक छोटी-सी गलती भी पूरी न्याय व्यवस्था की साख पर सवाल खड़ा कर सकती है।आज के डिजिटल युग में, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बदलता वैश्विक परिदृश्य कानून के स्वरूप को निरंतर नया आकार दे रहे हैं, क्या केवल पुरानी किताबों के ज्ञान से न्याय की रक्षा संभव है? सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश कि वकीलों के लिए 'कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन' अनिवार्य हो और एक 'नेशनल लीगल एकेडमी' की स्थापना की जाए, भारतीय न्याय व्यवस्था की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर ले जाने की दिशा में एक साहसी और दूरदर्शी कदम है। कानून का पेशा केवल बहस करना नहीं है, बल्कि यह एक 'पवित्र विश्वास' है, जिसे बनाए रखने के लिए निरंतर विकास अनिवार्य है। आज के इस 'ज्ञान युग' में, कानूनों, तकनीक और विनियामक ढांचों में इतनी तेजी से बदलाव हो रहे हैं कि वर्षों पहले अर्जित किया गया ज्ञान आज पूरी तरह अप्रासंगिक हो सकता है। इसके साथ ही, कानूनी क्षेत्र में तकनीकी पिछड़ापन एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, जिसे दूर करना समय की मांग है। आज के आधुनिक वकील के लिए ई-कोर्ट्स, वर्चुअल हियरिंग, ऑनलाइन केस मैनेजमेंट और कानूनी डेटा विश्लेषण में दक्ष होना केवल कौशल का प्रदर्शन नहीं, बल्कि आवश्यकता है। इसके अलावा, अदालती शिष्टाचार, मुवक्किल के प्रति जवाबदेही और अनैतिक प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए निरंतर नैतिक प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस पेशे की गरिमा हमेशा बनी रहे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में 'मैन्डेटरी कंटीन्यूइंग लीगल एजुकेशन' लागू है। वहां वकीलों के लिए अपने लाइसेंस को बनाए रखने हेतु हर साल निश्चित घंटों की कानूनी शिक्षा या सेमिनार में भाग लेना अनिवार्य होता है। इसी तरह, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में बार एसोसिएशन और सरकार के सहयोग से 'निरंतर पेशेवर विकास' कार्यक्रमों को कड़ाई से लागू किया जाता है, जहां इन क्रेडिट्स को पूरा न करने पर वकील के अभ्यास करने के अधिकार को अस्थायी रूप से निलंबित तक किया जा सकता है।भारत में कानूनी पेशे का विस्तार तेजी से हुआ है, लेकिन गुणवत्ता उस अनुपात में नहीं बढ़ सकी है। आज देश में वकीलों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है और हर वर्ष हजारों युवा कानून की डिग्री लेकर इस क्षेत्र में आ रहे हैं। दूसरी ओर, भारतीय अदालतों में लंबित मामलों का बोझ 5 करोड़ से भी अधिक हो चुका है। वकीलों की संख्या में अनियंत्रित वृद्धि के कारण प्रति व्यक्ति 'प्रोफेशनल स्किल डेवलपमेंट' के अवसर सीमित हो गए हैं। 'नेशनल लीगल एकेडमी' का उद्देश्य केवल वकीलों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें निरंतर प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से 'सक्षम वकीलों की फौज' में बदलना है। यह एकेडमी नए वकीलों के लिए एक 'मेंटरशिप हब' के रूप में कार्य करेगी, जहां वरिष्ठ अधिवक्ता अपने व्यावहारिक अनुभव साझा करेंगे। इस प्रयास से किताबी ज्ञान और अदालती हकीकत के बीच की खाई मिटेगी और मुकदमों के जल्द निस्तारण की दर में 15 से 20 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हो सकेगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कानूनी पेशे के मानकों को ऊंचा उठाने के लिए एक 'सुपर-रेगुलेटर' के रूप में अपनी भूमिका को सशक्त बनाना होगा। इसके कार्यान्वयन हेतु सबसे पहले वकीलों के लिए एक अनिवार्य क्रेडिट-आधारित प्रणाली लागू की जानी चाहिए, जिसके तहत हर वकील के लिए प्रतिवर्ष 20 से 30 घंटे का प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य हो। इस शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए एक हाइब्रिड लर्निंग मॉडल अपनाना आवश्यक है, जहां नेशनल लीगल एकेडमी को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जोड़कर दूरदराज के क्षेत्रों के वकीलों तक पहुंचाया जा सके। एकेडमी की सफलता के लिए 'सार्वजनिक-निजी भागीदारी' का मॉडल सबसे प्रभावी होगा। इसमें शीर्ष लॉ फर्मों और अनुभवी वकीलों को 'गेस्ट लेक्चरर' के रूप में जोड़कर व्यावहारिक अनुभव प्रदान किया जा सकता है। न्यायिक प्रणाली में 'नेशनल लीगल एकेडमी' की स्थापना एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो कानूनी पेशे को केवल 'पढ़ाई' तक सीमित न रखकर इसे एक 'थिंक टैंक' में बदल सकती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इसे अधिकारों के हनन के बजाय 'अधिकारों के विस्तार' के रूप में देखना चाहिए।

स्वामी-स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ला द्वारा अनवर ऑफसेट एम- 58, 59 बेसमेंट विकासदीप बिल्डिंग स्टेशन रोड लखनऊ से मुदित ई-4 सेक्टर-एम/29 अपोजिट उस्मान एन्क्लेव, अलीगंज-लखनऊ 226024 से प्रकाशित, संपादक-राजीव कुमार शुक्ला , मो0-9511151254
Mail: news@swatantraprabhat.com, RNI No: UPHIN/2019/79073 इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी आर वी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायीं। किसी भी कानूनी विवाद का निपटारा न्यायलय जनपद लखनऊ ही होगा।

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान खैराबाद में विदाई एवं सम्मान समारोह संपन्न

अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाने में कोई विलम्ब न करें :- संतोष कुमार मिश्रा वरिष्ठ प्रवक्ता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

खैराबाद सीतापुर। स्थानीय जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ तथा पूर्व माध्यमिक जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ खैराबाद के द्वारा संयुक्त रूप से पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र की पदोन्नति एवं रायबरेली के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर स्थानांतरण के अवसर पर विदाई एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया।इस अवसर पर जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित, प्रवक्ता मनीष पांडेय, ज़िला उपाध्यक्ष प्राथमिक वंदना दीक्षित, डॉक्टर अनुपम मिश्र, ब्लॉक अध्यक्ष जूनियर नरेश मिश्रा, प्राथमिक अध्यक्ष पवन कुमार सिंह, संरक्षक बृजेन्द्र कुमार टी पी सिंह,वरिष्ठ उपाध्यक्ष काजिम हुसैन सिद्दीकी, राज्य पुरस्कार प्राप्त नीलम कुमारी, ए आर पी संजीव पटेरिया, वीरेन्द्र कुमार मुख्य रूप से उपस्थित रहे कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ शिक्षक योगेन्द्र पांडेय ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर मालार्पण एवं द्वीप प्रज्जवलित करके पूर्व खण्ड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्र एवं अन्य ने किया तत्पश्चात मुख्य अतिथि का माल्यार्पण तथा तिलक लगाकर स्वागत किया गया। तथा सरस्वती वंदना रुबीना बानो, नीलम कुमारी, शशि बाला ने कराई,ज्ञात हो कि संतोष कुमार मिश्र ने खैराबाद ब्लॉक में 2 अगस्त 2024 को कार्यभार ग्रहण किया था इससे पहले श्री मिश्र महोली, कसमंडा, आदि ब्लॉक में भी रह चुके थे जबकि पहली नियुक्ति 1998 में हुई थी।,श्री मिश्र ने अपने संबोधन में कहा कि मैंने कभी किसी को बिला वजह परेशान नहीं किया और किसी को कार्यालय बुलाने का भी कार्य न करके सीधे उसके कार्य को पूरा किया ताकि उसे दौड़ना न पड़े , यहां के शिक्षकों में प्रेम और संस्कार बहुत अच्छे हैं दूसरों की इज़्ज़त और उनका सम्मान करने में कोई कमी नहीं रखते विशेष रूप से आज की यह शिक्षकों की भीड़ और प्रेम व उत्साह को देख कर बहुत प्रसन्नता हुई है और सभी को आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग सदैव स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। इस अवसर पर दोनों संगठनों की ओर से ढेरों उपहार दिए गए तथा व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षिकाओं तथा शिक्षकों ने दिया जबकि संकुल धरैंचा की ओर से श्री मिश्र को शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करने के लिए पण्डित दीन दयाल उपाध्याय अवार्ड से सम्मानित किया गया। नोडल संकुल शिक्षक काज़िम हुसैन तथा संकुल शिक्षक हसन जमाल रिज़वी फ़ैज़ुल हसन, रुचि तिवारी सरिता रानी वर्मा सुरेंद्र कुमार जितेन्द्र कुमार मनी तिवारी ने स्मृति चिन्ह तथा उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में पंकज कुमार रावत रमेश रस्तोगी आलोक कुमार प्रमोद यादव पवन कुमार सिंह मंत्री अमित त्रिपाठी सौरभ जायसवाल जमशेद आलम प्रदेश अध्यक्ष अपूर्व दीक्षित ने कहा कि शिक्षकों के पार्टी इतना लगाव और सहयोग करने वाला अधिकारी नहीं देखा वाक़ई श्री मिश्र सम्मान पाने के हकदार हैं जबकि टी पी सिंह और मनीष पांडेय ने आपके साहस और आपकी हिम्मत की सराहना करके हमेशा याद रखने की बात कही, अन्य संबोधन करने वालों में काज़िम हुसैन,इशरत अली, रुबीना बानो, नीलम कुमारी, वंदना दीक्षित,अनुपम मिश्र, संजीव पटेरिया, वीरेन्द्र, प्रतिमा मिश्रा आदि हैं जबकि स्वागत भाषण नरेश मिश्रा ने तथा आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन पवन कुमार सिंह ने व्यक्त किया।

'एक पेड़ मां के नाम' अभियान को मिली नई ऊंचाई, सभी ग्राम पंचायतों में हुआ वृहद स्तर पर पौधारोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के विकास खंड मोहनलालगंज में रविवार को शासन के निर्देशानुसार वृहद वृक्षारोपण अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। अभियान के अंतर्गत विकास खंड की सभी ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं ग्रामीणों की सहभागिता से बड़े स्तर पर पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के संकल्प को साकार करने के उद्देश्य से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत पौधे रोपकर लोगों को अधिक से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का मुख्य आयोजन ग्राम पंचायत उत्तरगांव स्थित गंगा सागर अमृत सरोवर परिसर में संपन्न हुआ, जहां ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश शुक्ला 'विन्ध्येश्वरी', माननीय उपायुक्त श्रम रोजगार (वीबी जी राम जी), लखनऊ सुशील कुमार सिंह तथा खंड विकास अधिकारी शिवकुमार ने संयुक्त रूप से 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत पौधरोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उपस्थित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण को संतुलित रखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ व सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी धरोहर भी हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिकाधिक पौधे लगाने तथा उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष के रूप में विकसित करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी (एपीओ) उदय राज शर्मा, तकनीकी सहायक, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सेवक मथुरा प्रसाद यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। पूरे विकास खंड में उत्साहपूर्ण वातावरण के बीच विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए तथा सभी ने हरित मोहनलालगंज के निर्माण का संकल्प दोहराया। वृक्षारोपण अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण, जलवायु संतुलन और प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन की दिशा में विकास खंड मोहनलालगंज ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया।

नवागत खंड शिक्षा अधिकारी के स्वागत में शिक्षक संघ का भव्य समारोह आयोजित

शिक्षकों को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तत्काल बताएं सिमी निगार खण्ड शिक्षा अधिकारी मछरेहटा

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मछरेहटा सीतापुर। नवागत खण्ड शिक्षा अधिकारी के प्रथम दिन पने कार्यालय में आगमन पर जूनियर हाईस्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ मछरेहटा ने खण्ड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार मैडम का उनके कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया,इस दौरान शिक्षक संघ के पदाधिकारियों द्वारा मैडम को बुके भेंट कर अत्यंत आत्मीयता के साथ स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। स्वागत समारोह के उपरांत शिक्षक संघ और खण्ड शिक्षा अधिकारी के बीच ब्लॉक में शिक्षा की गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर एक सकारात्मक बैठक हुई। जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष पवन शुक्ल व प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकेश दीक्षित द्वारा आदरणीया खंड शिक्षा अधिकारी महोदया से बीआरसी व विद्यालय स्तर शिक्षकों की समस्याओं पर सार्थक चर्चा हुई, महोदया ने आशान्वित किया कि शिक्षकों की समस्याओं का तत्काल निराकरण कराया जाएगा। इस स्वागत कार्यक्रम में पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ मछरेहटा के अध्यक्ष पवन शुक्ल,मंत्री सुनील यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मुकेश दीक्षित, प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष संदीप यादव जी, उपाध्यक्ष आरती श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष राशिद हुसैन,वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरज मिश्रा, लोकेंद्र कटारा, सियालाल, संतोष शुक्ल जी सहित ब्लॉक कार्यकारिणी के तमाम सम्मानित पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

विराम खंड-5 में 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत विशाल वृक्षारोपण महाअभियान का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में 12 जुलाई 2026 उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणादायी आह्वान पर 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के अंतर्गत आज रविवार, 12 जुलाई 2026 को सायं 5:00 बजे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क (राम भवन के सामने), विराम खंड-5, गोमती नगर, लखनऊ में जन कल्याण समिति, विराम खंड-5 द्वारा विशाल वृक्षारोपण महाअभियान का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समिति के पदाधिकारियों एवं क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता करते हुए अपने हाथों से पौधारोपण किया तथा पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि प्रत्येक पौधा केवल एक वृक्ष नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ वायु, हरियाली एवं सुरक्षित पर्यावरण का संकल्प है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉ. भरत राज सिंह (अध्यक्ष), कर्नल पाण्डेय, (महासचिव-महासमिति), संजय निगम, (सचिव, महासमिति), सी.जी. नायर, (सचिव महासमिति), के.के. मौर्य, (कल्चरल सचिव महासमिति), विजय चोपड़ा (उपाध्यक्ष, विराम -5), अरुण त्रिवेदी (कल्चरल सचिव, विराम-5), अधिवक्ता नित्यानंद पाण्डेय (सचिव), प्रवीण मिश्रा (संयुक्त सचिव), अतुल जौहरी (कोषाध्यक्ष), डॉ. आर.पी. शर्मा, सदस्य, राकेश तिवारी (पूर्व,कोषाध्यक्ष), प्रभात श्रीवास्तव (संगठन सचिव), मनोज शर्मा (प्रचार सचिव), आचार्य अशोक तिवारी, प्रवीण खंडेलवाल, एवं चन्दन सहित समिति के सदस्य एवं क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। जन कल्याण समिति ने सभी उपस्थित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं उनके संरक्षण का संकल्प दोहराया तथा पर्यावरण संरक्षण के इस जनआंदोलन को निरंतर आगे बढ़ाने का आह्वान किया।

अपराधियों में कानून का डर और जनता में विश्वास ही असली पुलिसिंग : दिग्गज

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राष्ट्रीय अपराध रोकथाम परिषद एवं अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में होटल मेज़बान, लाटूश रोड पर 'जनता में पुलिस की विश्वसनीयता कैसे कायम हो' विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित हुआ। पूर्व डीजीपी सूर्य प्रकाश शुक्ला ने कहा कि अपराधियों में कानून का भय और जनता में पुलिस पर विश्वास ही असली पुलिसिंग है। पूर्व आईजी राजीव मल्होत्रा ने तकनीक के साथ संवेदनशील पुलिसिंग पर जोर दिया, जबकि पूर्व न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने निष्पक्ष जांच और पुलिस-न्यायपालिका के बेहतर समन्वय को आवश्यक बताया। परिषद के चेयरमैन डॉ. अरविंद चित्तौड़िया ने अपराध रोकथाम में समाज और मीडिया की भूमिका पर प्रकाश डाला। अखिल भारतीय पत्रकार एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र मिश्र ने पुलिस को जनसेवक की भूमिका निभाने और फरियादियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

संक्षिप्त खबरें

विधायक निर्मल वर्मा व अधिकारियों द्वारा कई स्कूलों में छात्र-छात्राओं के साथ किया गया वृक्षारोपण

बिसवां,सीतापुर। क्षेत्रीय विधायक निर्मल वर्मा एवं क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल श्रीवास्तव, खंड विकास अधिकारी धनजय सिंह,सहायक विकास अधिकारी राजेश कुमार श्रीवास्तव के द्वारा बिसवां ब्लाक की ग्राम पंचायत पुरवा दासा के मजरा इटदहा, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय मानपुर, स्वामी विवेकानंद इंटर कालेज मानपुर, एलपिस ग्लोबल स्कूल बिसवां के छात्र एवं छात्राओं के साथ मे वृक्षा रोपण किया। वृक्षा रोपण कार्यक्रम के अंत मे वन क्षेत्राधिकारी अतुल श्रीवास्तव ने सभी आगूंतको के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर एस के शैलेश, प्रद्युमन तिवारी, राजनाथ यादव, अनरुद्ध कुमार , अभय प्रताप मौर्या, रमाकांत मौर्य, अख्तर अली,रामनरेश आदि सहित बड़ी संख्या मे ग्रामीणों ने सहभागिता की। बिसवां ब्लाक की ग्राम पंचायतो मे बड़ी संख्या मे वृक्षा रोपण किया गया।

बक्शी का तालाब इंटर एवं कृषि महाविद्यालय मे वृक्षारोपण।

सीतापुर। वृक्षारोपण महाअभियान एक पेड़ मां के नाम पर इंटर कॉलेज एवं चंद्रभान गुप्त कृषि महाविद्यालय में वृक्षारोपण महा अभियान की शुरुआत की गई। बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज के प्रांगण में डॉ बी पी राम निदेशक उद्यान विभाग उत्तर प्रदेश शासन, डॉ डीपी सिंह जिला उद्यान अधिकारी, दिलीप कुमार वरिष्ठ उद्यान निरीक्षक, रमेश यादव प्रभारी उद्यान बीकेटी आदि के साथ विद्यालय प्रधानाचार्य अशोक कुमार बाजपेई पूर्व प्रधानाचार्य डॉ? के के शुक्ला,डॉ? राजेश मिश्रा, पन्नालाल गुप्ता, अनिल कुमार गौतम, हरिश्चंद्र सिंह रामजी यादव, अजय कुमार, चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के डॉ जसकरन, डॉ हृदय नारायण तिवारी, रणजीत सिंह, प्रेम बाबू चौरसिया तथा विद्यालय के सभी कर्मचारी व छात्र- छात्राओं ने बड़े उत्साह से वृक्षारोपण किया और उनकी सुरक्षा हेतु ट्री गार्ड लगाए। चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ सत्येंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बक्शी का तालाब इंटर कॉलेज में देसी आम , नीम महुआ, कैथा, बेल चिलवल तथा बालम खीरा, सहजन, अमरूद सहित 51 पौधे रोपित किए गए तथा चंद्रभानु गुप्त कृषि महाविद्यालय के हाजीपुर कृषि फार्म पर 100 से अधिक पौधे लगाए गए।

साहित्य सृजन संस्थान, बिसवां द्वारा जरूरतमंद, मेधावी बच्चों को निःशुल्क वितरित की गई पाठ्य पुस्तकें

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां (सीतापुर)। शैक्षिक, सामाजिक, साहित्यिक सरोकारों को समर्पित अ. भा. संस्था 'साहित्य सृजन संस्थान' द्वारा क्षेत्र बच्चों के शैक्षिक विकास के लिए बिसवां में निकट पशु चिकित्सालय, तहसील रोड पर स्थापित 'सृजन पुस्तकालय' में (हाई स्कूल इंटर के छात्र, छात्राओं को) निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी एवं स्कूल बैग उपलब्ध कराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगरपालिका, चेयरमैन, पुष्पू जायसवाल उपस्थित रहे। संस्थान द्वारा उन्हें अंगवस्त्र, स्मृतिचिह्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। समाजसेवी गिरिधर अग्रवाल, सौरभ बंसल के द्वारा कृष्णा देवी गर्ल्स कॉलेज की कुछ छात्राओं को उनकी पाठ्यक्रम की पुस्तकें, स्टेशनरी और स्कूल बैग प्रदान किया गया। इसी क्रम में कुछ अन्य बच्चों को उनकी स्कूल किट उनके विद्यालय भेजी गई। इस अवसर चेयरमैन ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकालय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हैं और एक प्रबुद्ध पाठक वर्ग का निर्माण करते हैं। सृजन पुस्तकालय का यह प्रयास सराहनीय है। हमारी शुभकामनाएं और भरपूर सहयोग संस्थान को सदैव सुलभ रहेगा। संस्थान के संस्थापक /अध्यक्ष साहित्यकार संदीप मिश्र सरस ने बताया कि संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष क्षेत्र के मेधावी जरूरतमंद छात्र-छात्राओं को निःशुल्क स्कूल बुक किट उपलब्ध कराई जाती है। ये बच्चे अपनी मेधा के बल पर सफलता अर्जित करके बिसवां का नाम पूरी दुनिया में जब रोशन करेंगे तो हमारे संस्थान का संकल्प सार्थक हो जाएगा। कार्यक्रम में कृष्णा देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य लक्ष्मी देवी, उप प्रधानाचार्य उषा मिश्रा, गंगा स्वरूप मिश्र, एडवोकेट मनोज गुप्ता, श्रीकांत मिश्रा, नीरज मिश्रा सभासद, हरिशंकर त्रिवेदी मुकुंद पांडेय, अमन बाजपेई आदि एवं बच्चों के अभिभावक उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि पुस्तकालय में विभिन्न भाषाओं की साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक पुस्तकों के साथ-साथ पर्याप्त कंपटीशन बुक्स की व्यवस्था है। प्रतिवर्ष विभिन्न महाविद्यालयों के अन्यान्य शोध छात्र छात्राएं पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध पुस्तकों से अपने लघु शोध प्रबंध तैयार करते हैं। सृजन पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर बच्चों को विभिन्न स्कूल, कोचिंग सेंटर में एडमिशन एवं छूट का सहयोग दिलाया जाता है और छात्र-छात्राओं के लिए मोटिवेशनल क्लासेस एवं करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं। अब पुस्तकालय में कंप्यूटर प्रशिक्षण की भी व्यवस्था संचालित हो गई है।

मानस एनक्लेव फेस-2 में भारत माता पार्क पर योग शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। लखनऊ राजधानी लखनऊ के मानस एनक्लेव फेस-2 के अध्यक्ष आमोद सिंह के नेतृत्व में भारत माता पार्क में एक भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सोसायटी के महिला एवं पुरुष सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर योगाभ्यास किया तथा स्वस्थ जीवन का संकल्प लिया। कार्यक्रम में भारतीय योग संस्थान के जिला प्रधान अरुण जैन ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया। उन्होंने बताया कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ, मन शांत एवं जीवन संतुलित रहता है। उन्होंने सभी से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस अवसर पर मानस एनक्लेव फेस-2 के अध्यक्ष आमोद सिंह ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं अमूल्य विरासत है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में प्रत्येक नागरिक के लिए योग करना अत्यंत आवश्यक है। नियमित योग से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि मानसिक तनाव भी दूर होता है और व्यक्ति ऊर्जावान एवं सकारात्मक जीवन जीता है। योग शिविर के उपरांत सोसायटी के मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया गया। कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट) एवं ट्रॉफी प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया। अध्यक्ष आमोद सिंह एवं अन्य पदाधिकारियों ने विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए उनके परिश्रम और उपलब्धियों की सराहना की। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों ने प्रतिदिन योग करने तथा अपने परिवार और समाज के अन्य लोगों को भी योग के प्रति जागरूक करने का संकल्प लिया। योग शिविर एवं सम्मान समारोह ने उपस्थित लोगों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक एकता के प्रति सकारात्मक संदेश प्रसारित किया।

वृक्षारोपण दिवस पर कौशल विकास मिशन मुख्यालय में पौधरोपण, हरित भविष्य का दिया संदेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। वृक्षारोपण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) मुख्यालय, लखनऊ में रविवार को पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने परिसर में पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण और हरित भविष्य का संदेश दिया तथा सभी से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनके संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इस अवसर पर पुलकित खरे ने कहा कि कौशल विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण भी हमारा सामाजिक दायित्व है। एक स्वस्थ और हरित पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्ज्वल भविष्य की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि केवल पौधे लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी नियमित देखभाल कर उन्हें वृक्ष बनाना भी सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाने की दिशा में भी कार्य कर रहा है।

विद्युत मजदूर संगठन की केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर गरजे पदाधिकारी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ स्थित संगठन भवन, जी-107 हम्बरा अपार्टमेंट, श्यामा चौराहा में रविवार को विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश की केंद्रीय कार्यकारिणी बैठक संगठन के अध्यक्ष विमलचंद्र पाण्डेय की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों ने विद्युत कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों से जुड़े विभिन्न लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सरकार एवं पावर कॉरपोरेशन से शीघ्र समाधान की मांग की। बैठक को संबोधित करते हुए संगठन के मुख्य महामंत्री श्रीचन्द्र ने कहा कि कार्यकारी सहायक (टीजी-2) एवं समकक्ष कर्मचारियों की वेतन विसंगति वर्षों से लंबित है, जबकि समयबद्ध पदोन्नति भी नहीं की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानांतरण नीति की अनदेखी कर कर्मचारियों का जिलों से बाहर स्थानांतरण किया गया है। साथ ही वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर बड़े पैमाने पर पदों की कटौती और हजारों संविदा कर्मियों की सेवा समाप्त किए जाने से विद्युत व्यवस्था प्रभावित हुई है। कर्मचारियों की कमी के कारण उपभोक्ताओं का दबाव बढ़ा है और कई स्थानों पर कर्मचारियों के साथ मारपीट जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मृतक आश्रित भर्ती के अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था समाप्त होने से अनेक परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा चयनित अवर अभियंताओं की वरिष्ठता सूची अब तक जारी नहीं की गई है तथा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बावजूद प्रथम एसीपी का लाभ भी नहीं दिया गया है। बैठक के अंत में संगठन के अध्यक्ष विमलचंद्र पाण्डेय ने बताया कि सरकार ने संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए सेवा निगम का गठन किया है, लेकिन अभी तक ऊर्जा विभाग को इसमें शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऊर्जा विभाग को भी सेवा निगम के दायरे में लाने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 की हड़ताल के दौरान सेवा से हटाए गए संविदा कर्मियों तथा वर्टिकल व्यवस्था के नाम पर हटाए गए कर्मचारियों को तत्काल पुनः सेवा में लिया जाए। साथ ही आंदोलन के दौरान कर्मचारियों पर हुई उत्पीड़नात्मक कार्रवाई समाप्त कर उनका सम्मान बहाल किया जाए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों की जायज मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो संगठन व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक का संचालन प्रदेश प्रभारी आर.सी. पाल ने किया। इस अवसर पर कार्यवाहक अध्यक्ष आलोक सिन्हा, शोएब हसन, प्रताप सिंह, एस.के. सिंह, आर.वाई. शुक्ला, मोहन बाबू आर्य, जलीलुर्रहमान, अशोक गुप्ता, राहुल कुमार, विनोद श्रीवास्तव, संदीप कुमार, दीपक कश्यप, ज्ञानेन्द्र शर्मा, कपिल सारस्वत, अवनीश श्रीवास्तव, यशपाल सिंह, रविकांत, आरिफ बेग, पुनीत राय, प्रेम पाल, अरविन्द कुमार, चंद्रकांत, वेद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए।

ग्राम उतरावां में विकास कार्यों को मिली नई रफ्तार

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

मोहनलालगंज (लखनऊ)। राजधानी लखनऊ के ब्लाक मोहनलालगंज की ग्राम पंचायत उतरावां में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए क्षेत्रीय विधायक अमरेश कुमार रावत ने गौशाला से बाबा कुटी तक निर्मित सड़क का विधिवत फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर लगातार कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह सड़क बनने से ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा मिलेगी तथा धार्मिक स्थल बाबा कुटी तक पहुंचना भी आसान होगा। लोकार्पण समारोह के दौरान क्षेत्रवासियों ने विधायक का फूल-मालाओं से स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व मण्डल अध्यक्ष दीपू बाजपेई, सुधांशु सिंह, (जिलाध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक) राजेश कुमार रावत , प्रदीप सिंह, समेसी ग्राम प्रधान अशोक कुमार रावत, अभिषेक रावत सहित अनेक गणमान्य नागरिक एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। उपस्थित लोगों ने क्षेत्र में कराए जा रहे विकास कार्यों की सराहना करते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार जनहित के कार्य निरंतर जारी रहने की अपेक्षा व्यक्त की। समारोह का वातावरण उत्साहपूर्ण रहा और ग्रामीणों ने विकास कार्य के लिए विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया।

होर्मुज में जहाज पर हमले के बाद अमेरिका का ईरान पर बड़ा सैन्य प्रहार

140 ठिकानों पर अमेरिकी हवाई हमले; बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और यूएई पर मिसाइल-ड्रोन हमले, क्षेत्र में तनाव चरम पर

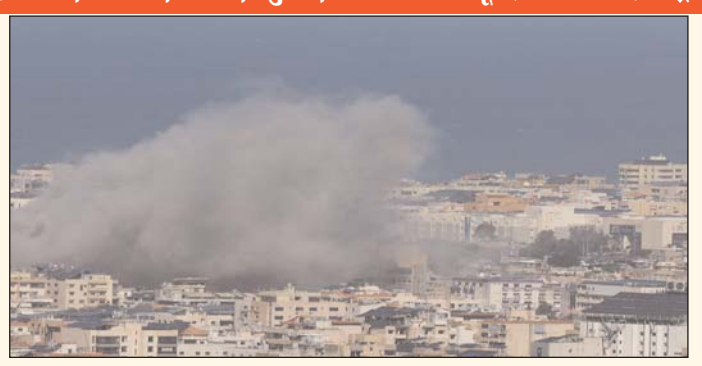

एजेंसी। होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कंटेनर जहाज पर हुए हमले के बाद अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया। अमेरिका ने रविवार तड़के ईरान के करीब 140 सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने बताया कि उसके हमलों में ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग स्थल, गोला-बारूद भंडार, संचार केंद्र और अन्य सैन्य प्रतिष्ठान नष्ट किए गए। सेंटकॉम के अनुसार, इस कार्रवाई का उद्देश्य होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक जहाजों और असैन्य नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना तथा ईरान की हमले की क्षमता को कमजोर करना था। इससे पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य में एक कंटेनर जहाज पर हमला किया था, जिससे उसमें आग लग गई और चालक दल को जहाज छोड़कर सुरक्षित निकलना पड़ा। इस घटना के बाद दोनों देशों के बीच पहले से जारी तनाव और अधिक बढ़ गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध को लेकर बना अंतरिम समझौता अब समाप्त हो चुका है। वहीं अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने सोशल मीडिया पर कहा कि 'ईरान ने गलत विकल्प चुना है और अब उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। ' दूसरी ओर, ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कलीबाफ ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि एकतरफा समझौतों का दौर समाप्त हो चुका है और अब अमेरिका को अपने कदमों का परिणाम भुगतना होगा। अमेरिका ने पिछले एक सप्ताह में ईरान के खिलाफ तीन चरणों में हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी पक्ष का कहना है कि ये कार्रवाई होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के लगातार हमलों के जवाब में की गई है। ईरान की जवाबी कार्रवाई के दौरान कतर, बहरीन, कुवैत, ओमान और यूएई में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। कतर की सेना ने दावा किया कि उसने अधिकांश मिसाइल और ड्रोन हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। कतर के गृह मंत्रालय के अनुसार, हमलों को नाकाम करने के दौरान गिरे मलबे की चपेट में आने से एक बच्चे समेत तीन लोग घायल हो गए। कुवैत की सेना ने भी कई हमलों को विफल करने का दावा किया है। वहीं बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय के कारण तीसरी बार मिसाइल हमले की चेतावनी जारी करनी पड़ी। ओमान के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में भी ड्रोन हमलों की सूचना मिली है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात के कई इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ईरान ने दोहराया है कि होर्मुज जलडमरूमध्य पर उसका नियंत्रण होना चाहिए और वहां से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने का उसे अधिकार है। यही मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी संभावित वार्ता में सबसे बड़ी बाधा बनता जा रहा है।

21 जुलाई की रैली पर बंगाल में सियासी संग्राम, भाजपा ने टीएमसी पर बोला हमला

भाजपा नेता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में 1993 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती हैं तो सबसे पहले जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि एस्प्लेनेड जैसे व्यस्त इलाके में रैली आयोजित करने से आम जनता को भारी असुविधा होगी। यदि टीएमसी अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाना चाहती है तो उसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

आसनसोल(एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में 21 जुलाई को होने वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के 'शहीद दिवस' कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा नेता एवं राज्य की शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को टीएमसी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी अब पहले जैसी नहीं रही, बल्कि 'टुकड़े-टुकड़े गैंग' बन गई है। उन्होंने टीएमसी को एस्प्लेनेड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रैली कर अपनी वास्तविक ताकत दिखाने की चुनौती दी। आसनसोल में मीडिया से बातचीत के दौरान अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 21 जुलाई के कार्यक्रम से भाजपा को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पश्चिम बंगाल की जनता को यह जानने का अधिकार है कि 21 जुलाई 1993 को वास्तव में क्या हुआ था। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उस घटना की जांच के लिए आयोग गठित करने और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने का वादा किया था, लेकिन आज तक रिपोर्ट सामने नहीं लाई गई। भाजपा नेता ने कहा कि यदि मुख्यमंत्री वास्तव में 1993 के शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहती हैं तो सबसे पहले जांच आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि एस्प्लेनेड जैसे व्यस्त इलाके में रैली आयोजित करने से आम जनता को भारी असुविधा होगी। यदि टीएमसी अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाना चाहती है तो उसे ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी पहले ऐसी ही सलाह दे चुके हैं। टीएमसी ने इस वर्ष भी अपनी पारंपरिक 'शहीद दिवस' रैली कोलकाता के एस्प्लेनेड में आयोजित करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि, कोलकाता पुलिस ने यातायात व्यवस्था प्रभावित होने का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद पार्टी ने अनुमति के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट का रुख किया है। वहीं, ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी के बागी गुट को एस्प्लेनेड स्थित गांधी प्रतिमा के निकट अलग 'शहीद दिवस' कार्यक्रम आयोजित करने की पुलिस से अनुमति मिल चुकी है। तृणमूल कांग्रेस प्रत्येक वर्ष 21 जुलाई को 'शहीद दिवस' मनाती है। यह आयोजन वर्ष 1993 में हुई पुलिस फायरिंग की घटना की स्मृति में किया जाता है, जिसमें ममता बनर्जी के नेतृत्व में निकाली गई युवा कांग्रेस की रैली के दौरान 13 कार्यकर्ताओं की मौत हुई थी। वर्षों से कोलकाता के एस्प्लेनेड स्थित विक्टोरिया हाउस के सामने आयोजित होने वाली यह रैली टीएमसी के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में मानी जाती है, जिसमें राज्यभर से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल होते हैं।

प्रियंका-दीपिका के बाद दिशा पत्नी की हॉलीवुड में एंट्री, इस सुपरनैचरल थ्रिलर से करेंगी डेब्यू

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी अपनी अदाकारी का जलवा बिखरने के बाद जल्द ही हॉलीवुड में तहलका मचाने जा रही हैं। हाल ही एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान दिशा ने हॉलीवुड में डेब्यू को लेकर खुलकर अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से उनके हाथ ये विदेशी मूवी आई है। भारतीय सिनेमा में अपनी पहचान बना चुकी अभिनेत्री दिशा पाटनी अब हॉलीवुड में कदम रखने जा रही हैं। प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, अली फजल और अनुपम खेर के बाद वह भी हॉलीवुड में अपनी टैलेंट का प्रदर्शन करेंगी। दिशा की पहली हॉलीवुड फिल्म सुपरनैचुरल थ्रिलर 'हॉलीगार्ड्स सागाः द पोर्टल ऑफ फोर्स' होगी, जिसका निर्देशन ऑस्कर पुरस्कार विजेता केविन स्पेसी कर रहे हैं। इस परियोजना के माध्यम से दिशा वैश्विक दर्शकों के बीच अपनी नई पहचान बनाने के लिए तैयार हैं। हालिए एक इंटरव्यू में दिशा ने अपने हॉलीवुड सफर को लेकर बात की है। उन्होंने कहा- यह काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप कहां तक पहुंच पाते हैं। पश्चिमी देशों का सिनेमा ऑडिशन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। वहां काम पाने के लिए आपको ऑडिशन देना पड़ता है। इसमें किस्मत भी बड़ी भूमिका निभाती है कि कभी-कभी, वे (हॉलीवुड फिल्ममेकर) बस आपका पिछला काम देखते हैं और आपको प्रोजेक्ट या ऑडिशन का प्रस्ताव देते हैं। वैसे वहां काम करना व वीजा मिलना और दूसरे संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसमें में काफी तकनीकी चीजें शामिल रहती हैं। आखिर में वो वह एक अलग देश होता है, आपको मौके पर उपस्थित रहना होगा। यहां पर बैठकर, वहां अच्छे रोल नहीं पा सकते हैं। यहां से आप सिर्फ ऑनलाइन ऑडिशन दे सकते हैं, लेकिन वहां जाकर थोड़ा रुकना और उस पर काम करना सबसे अच्छा है। हालिए रिलीज अक्षय कुमार स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू जंगल में दिशा पाटनी नजर आई है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है। दिशा की अपकमिंग मूवी हॉलीवुड फिल्म हॉलीगार्ड सागाः द पोर्टल आफ फोर्स, वह आवारापन 2 में भी दिखेंगी, एक्ट्रेस की जोड़ी इमरान हाशमी संग बनी है। आवारापन 2 अगले महीने 14 अगस्त 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी।

यथार्थवादी फिल्मों में कलात्मक अभिव्यक्ति का सिकुड़ता दायरा

इन दिनों फिल्म 'सतलुज' का विवाद डिजिटल स्वतंत्रता के भ्रम पर उंगली उठा रहा है। मूल रूप से 'पंजाब '95' नाम से निर्मित और हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित यह फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालरा के जीवन और पंजाब के बेहद संवेदनशील दौर पर आधारित है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर ने इस फिल्म को लेकर कड़ा रुख अपनाया और निर्माताओं को लगभग 127 कट लगाने का निर्देश दिया। लंबे कानूनी और प्रशासनिक संघर्ष के बाद, फिल्म को 'सतलुज' नाम से एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज तो किया गया, लेकिन सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय संप्रभुता का हवाला देकर इसे डिजिटल स्पेस से भी हटा दिया गया।

यह घटनाक्रम इस धारणा को तोड़ता है, कि ओटीटी प्लेटफॉर्म गंभीर और यथार्थवादी सिनेमा के लिए स्वतंत्र खिड़की साबित होंगे। डिजिटल माध्यमों को अधिक उदार और सेंसरशिप से मुक्त माना जाता था, लेकिन आईटी नियमों में हाल के संशोधनों ने सरकारों को असीमित शक्ति दे दी कि वह 'सार्वजनिक व्यवस्था' या 'शांति भंग' की आशंका के आधार पर किसी भी डिजिटल सामग्री को प्रतिबंधित कर सके। ऐसी स्थिति में फिल्म निर्माता वित्तीय और कानूनी जोखिमों से बचने को अपनी रचनात्मकता को सीमित करने लगते हैं।भारतीय सिनेमा के इतिहास में कई प्रसंग हैं, जहां सेंसर बोर्ड से 'हरी झंडी' मिलने के बावजूद फिल्मों को थियेटर तक पहुंचने से रोका गया। यह प्रवृत्ति दर्शाती है कि सेंसरशिप केवल संस्थागत प्रक्रिया नहीं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दबावों से संचालित होती है। वर्ष 1993 के मुंबई बम धमाकों पर आधारित अनुराग कश्यप की फिल्म 'ब्लैक फ्राइडे' को सेंसर बोर्ड ने अनुमति दे दी थी, परंतु एक याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसके प्रदर्शन पर सशर्त अस्थाई रोक लगा दी थी। तर्क था कि फिल्म वास्तविक गवाहों और न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। इसी प्रकार, दीपा मेहता की फिल्म 'वाटर' जो वाराणसी की विधवाओं की दयनीय स्थिति का कथानक था, उसे देश में शूट नहीं करने दिया गया। भारी विरोध प्रदर्शनों के कारण उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था की दुहाई देकर इसकी शूटिंग रोक दी। इसे श्रीलंका में फिल्माया गया। आनंद पटवर्धन की डॉक्यूमेंट्री फिल्मों, विशेषकर 'राम के नाम' और 'फादर, सन एंड होली वॉर' के साथ तो यह संघर्ष दशकों लंबा चला। हालांकि, इन मामलों में न्यायपालिका ने हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में निर्णय देकर कला का मार्ग प्रशस्त किया।राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए फिल्मों को बलि का बकरा बनाने के प्रसंगों में प्रकाश झा की 'आरक्षण' और मधुर भंडारकर की 'इंदु सरकार' भी शामिल है। 'आरक्षण' को जातिगत तनाव की आशंका के चलते कुछ राज्यों में प्रतिबंधित किया गया, जबकि 'इंदु सरकार' को 1975 के आपातकाल की पृष्ठभूमि के कारण भारी राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा। संजय लीला भंसाली की 'पद्मावत' का विवाद राज्य सरकारों की लाचारी या राजनीतिक अवसरवाद का उग्र उदाहरण रहा है। सेंसर बोर्ड के कहने पर नाम बदलने और संशोधनों के बाद इसे 'यू/ए' सर्टिफिकेट दिया, इसके बावजूद हिंसक विरोध के आगे झुकते हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। अंततः सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप कर स्पष्ट करना पड़ा कि एक बार वैधानिक संस्था फिल्म को पास कर देती है, तो कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य की जिम्मेदारी है।

बीते दशकों की तुलना में अब सेंसरशिप का स्वरूप बदल चुका है। पहले जहां सेंसरशिप केवल 'केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड' (सेंसर) की कैंची तक सीमित थी, वहीं अब अधिक खतरनाक 'समानांतर सेंसरशिप' का उदय हो गया।

यह समानांतर व्यवस्था राजनीतिक दलों, धार्मिक संगठनों, वैचारिक समूहों और सोशल मीडिया की ट्रोल आर्मी के गठजोड़ से संचालित होती है।

एक पेड़ माँ के नाम 3.0' के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में 36,92,500 पौधों का सफल वृक्षारोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

अम्बेडकरनगर। आज दिन रविवार को वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 'एक पेड़ माँ के नाम 3.0' अभियान के अंतर्गत जनपद अम्बेडकरनगर में जिला वृक्षारोपण समिति एवं प्रभागीय वनाधिकारी/सचिव, जिला वृक्षारोपण समिति के तत्वावधान में वृक्षारोपण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। जनपद अम्बेडकर नगर को वर्ष 2026 हेतु आवंटित 36,92,500 पौधों के वृक्षारोपण लक्ष्य के अंतर्गत आज व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 कार्यक्रम का शुभारम्भ वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 की समीक्षा हेतु जनपद अम्बेडकर नगर के लिए नामित नोडल अधिकारी प्रांजल यादव, सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, उत्तर प्रदेश द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के कि.मी. 161 स्थित उम्मरपुर ग्राम सभा की भूमि पर 'एक पेड़ माँ के नाम' थीम के अंतर्गत पौधरोपण करके किया गया। इसी क्रम में जनपद के लिए नामित नोडल मंत्री, कैबिनेट मंत्री, मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, डॉ. संजय कुमार निषाद द्वारा अकबरपुर रेंज के ग्राम सभा लोहझरा, विकास खण्ड भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर में हरिशंकरी का पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर विधायक कटेहरी धर्मराज निषाद द्वारा महोगनी का पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में रामबाबा जूनियर हाई स्कूल के छात्र-छात्राओं द्वारा मनमोहक स्वागत गीत एवं लोकगीत प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर अन्य जनप्रतिनिधिगण, ग्राम प्रधान, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, प्रभागीय वनाधिकारी, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, एन.सी.सी. एवं एन.एस.एस. के कैडेटों ने पूर्ण उत्साह एवं मनोयोग के साथ महोगनी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधों का रोपण कर पर्यावरण संरक्षण एवं हरित भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया।

एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा किया गया पौधरोपण

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सुरियावा। जनपद में रविवार को वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के अंतर्गत 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के के अंतर्गत। नगर पंचायत सुरियावा केसहुआइन तालाब परनगर पंचायत अध्यक्ष सुरियावां विनय चौरसिया द्वारा पौधारोपण किया गया पौधारोपण करते हुए बताया कि पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास एवं स्वच्छ वातावरण का संदेश देते हुए लगाए गए पौधों की देखभाल करना बहुत जरूरी है कहा कि वृक्षारोपण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य के प्रति हमारी सतत जिम्मेदारी है इस मौके पर पंजाबी मोदनवाल गोपाल श्याम ललित उपाध्याय स्वरूप बिन्द सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे।

20 किलो गांजा के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक भी बरामद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ज्ञानपुर (भदोही)। मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत ज्ञानपुर पुलिस ने 20 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से तस्करी में प्रयुक्त एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के पर्यवेक्षण में रविवार को चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिंहपुर नहर मार्ग तिराहे पर घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। तलाशी के दौरान उसके पास से 20 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। इस संबंध में थाना ज्ञानपुर में मु0अ0सं0 178/2026 के तहत धारा 8/20/29 एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी का चालान न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है।

पांच लाख रुपये और पल्सर बाइक की मांग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ललितपुर। दहेज की अतिरिक्त मांग पूरी न होने पर विवाहिता के साथ मारपीट, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना तथा मायके पहुंचकर जबरन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर कराने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने पति, सास-ससुर, जेठ सहित पांच लोगों के खिलाफ बीएनएस एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआतला निवासी रामदास नरवरिया की पुत्री नीलम का विवाह 26 जून 2023 को थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम दैलवारा निवासी गजेंद्र पुत्र केरन सिंह के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था। विवाह में पीड़िता के परिजनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज भी दिया था, लेकिन आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति गजेन्द्र, ससुर केरन सिंह, सास रेखा, जेठ सीताराम तथा रिश्तेदार थाना बार के ग्राम मरौली निवासी मंगल ने अतिरिक्त दहेज के रूप में 5 लाख रुपये नकद और एक पल्सर मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर उसे लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उसके साथ मारपीट की जाती थी, पर्याप्त भोजन नहीं दिया जाता था तथा कई बार कमरे में बंद कर रखा गया। परिवार की इज्जत और वैवाहिक जीवन बचाने की उम्मीद में वह लंबे समय तक अत्याचार सहती रही, लेकिन आरोपियों का व्यवहार नहीं बदला। 11 अप्रैल 2026 को सभी आरोपियों ने मिलकर नीलम के साथ मारपीट की, उसके सोने-चांदी के जेवर छीन लिए और उसे घर से निकाल दिया। जाते समय आरोपियों ने चेतावनी दी कि जब तक वह 5 लाख रुपये और पल्सर बाइक लेकर नहीं आएगी, तब तक उसे घर में प्रवेश नहीं मिलेगा और वापस आने पर जान से मार दिया जाएगा। ससुराल से निकाले जाने के बाद नीलम अपने मायके ग्राम कुआतला में रहने लगी। आरोप है कि 8 जुलाई 2026 की शाम करीब चार बजे पति, सास-ससुर, जेठ और मंगल चार पहिया वाहन से उसके मायके पहुंचे। वहां आरोपियों ने विवाहिता पर जबरन तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने का दबाव बनाया। विरोध करने पर उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। शोर सुनकर गांव के महेन्द्र और सोनू ठाकुर मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर मामला शांत कराया। आरोप है कि जाते समय आरोपी दोबारा धमकी देकर गए कि यदि वह बिना दहेज के वापस आई तो उसकी हत्या कर देंगे और पति की दूसरी शादी कर देंगे। तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 85, 115(2), 352, 351(3) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 एवं 4 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया है।

कोतवाली क्षेत्र के ग्राम कुआतला निवासी रामदास नरवरिया की पुत्री नीलम का विवाह 26 जून 2023 को थाना बानपुर क्षेत्र के ग्राम दैलवारा निवासी गजेंद्र पुत्र केरन सिंह के साथ हिन्दू रीति-रिवाज से हुआ था।

कृषि विवि में वृक्षारोपण महायज्ञ बना मिसाल, कृषि मंत्री ने भी रोपे पौधे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कुमारगंज [अयोध्या]। हरित उत्तर प्रदेश के संकल्प को नई ऊंचाई देते हुए आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज ने वृक्षारोपण महायज्ञ-2026 के तहत एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। विश्वविद्यालय ने निर्धारित लक्ष्य से अधिक पौधरोपण किया। इस वृहद अभियान का शुभारंभ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एवं विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने पौधरोपण कर किया। इस दौरान पूरे विश्वविद्यालय परिसर के साथ-साथ सभी संचालित महाविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में पौधरोपण अभियान चलाया गया। शिक्षकों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं व एनसीसी के कैडेटों ने उत्साहपूर्वक इमली, जामुन, सागौन, आम, बेर, अमरूद, अमलतास, गुलमोहर, प्लास, कैथा, कटहल, पाकड़, पीपल जैसे छायादार, फलदार एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रजातियों के पौधे लगाए। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार वृक्षारोपण को जनभागीदारी का महाअभियान बना रही है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक यदि एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल का संकल्प ले, तो आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ, सुरक्षित और हरित वातावरण मिल सकेगा। बच्चे फल खाएंगे तो कुपोषण से दूर रहेंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय के इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे अन्य संस्थानों के लिए प्रेरणादायी बताया। कुलपति डॉ. ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवि मुख्य परिसर के लिए वृक्षारोपण का वृहद रोडमैप तैयार कराया जा रहा है जो जुलाई माह के अंत तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय कृषि शिक्षा, अनुसंधान और प्रसार गतिविधियों के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी समान महत्व दे रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित सभी महाविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों एवं शोध केंद्रों पर भी वृहद स्तर पर पौधरोपण किया गया। वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम वानिकी अधिष्ठाता डा. भगवानदीन, कृषि अधिष्ठाता डा. प्रतिभा सिंह, डीएसडब्ल्यू डा. डी. नियोगी व विभागाध्यक्ष डा. एस.के वर्मा के संयोजन में चलाया गया। इस मौके पर विधायक रामचंद्र यादव, विधायक चंद्रभानु पासवान, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, प्रखर गुप्ता प्रभागीय वनाधिकारी अयोध्या, प्रमोद कुमार वनाधिकारी कुमारगंज मौजूद रहे।